

प्रेषक,

सुबद्धन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,  
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुमाग:-1

देहरादून: दिनांक: ०१ जनवरी, 2013

विषय— वित्तीय वर्ष 2012-13 में आयोजनेतर पक्ष में सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-6109-10 नियो०/लेखा-बजट/2012-13 दिनांक 09 जनवरी, 2013 एवं अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या-209-10/सह०न्या०/2012-13/दिनांक 03 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सहकारिता विभाग के आयोजनेतर पक्ष के अन्तर्गत सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की विभिन्न मदों हेतु शासनादेश संख्या-608/XIV-1/2012-05(6)/2012 दिनांक 11अप्रैल, 2012 व शासनादेश संख्या-1196/XIV-1/2012-05(6)/2012 दिनांक 06 जुलाई, 2012 तथा सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आयोजनेतर पक्ष में शासनादेश संख्या-607/XIV-1/2012-05(7)/2012 दिनांक 16 अप्रैल, 2012 एवं शासनादेश संख्या-1685/XIV-1/2012-05(7)/2012 दिनांक 12जुलाई, 2012 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि में से संलग्न बी०एम० प्रपत्रानुसार पुनर्विनियोग सहित कुल रूपये 9,55,000/- (नौ लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तन तथा व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-45(NP)/XXVII-4/2013 दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय,  
श्री  
( सुबद्धन )  
सचिव।

संख्या:-१२ (१) / XIV-१ / २०१३, तददिनांक,

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग-४, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, देहरादून।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा / देहरादून।
6. निदेशक, एन०आइ०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,  
भेदा  
(रमेश कुमार)  
उप सचिव।